केदार नाथ मोतानी और अन्य

बनाम

प्रह्लाद राय और अन्य

(एस. आर. दास, सी.जे., एम. हिदायतुल्ला और के. सी. दास गुप्ता, जे.जे.)

धोखाधड़ी और अवैधता-बेनामी लेनदेन-धोखाधड़ी का इरादा था लेकिन प्रभावित नहीं किया गया-व्यक्ति को धोखाधड़ी के बारे में पता होना चाहिए लेकिन लेनदेन को रद्द नहीं करना चाहिए-लेनदेन के दौरान की गई अवैधता-अवैधता पर आधारित कार्रवाई का कारण नहीं-नियम के अपवाद।

1922 में कोर्ट ऑफ वार्ड्स के प्रबंधक ने आर को वर्षों की अवधि के लिए एक गाँव का पट्टा प्रदान किया पट्टे के खंड 4 द्वारा पट्टेदार ने प्रबंधक की सहमति के बिना किसी रैयत या अन्य किरायेदार के साथ भूमि का कोई समझौता नहीं करने का बीड़ा उठाया और यदि पट्टेदार के किसी रिश्तेदार या नौकर के साथ समझौता करने का प्रस्ताव किया गया था तो प्रबंधक को इस तथ्य का खुलासा किया। खंड 16 के तहत पट्टेदार या उसके रिश्तेदारों या उसके कर्मचारियों के नाम पर ली गई भूमि पट्टे की समाप्ति के बाद कोर्ट ऑफ वार्ड द्वारा फिर से शुरू की जाने के लिए उत्तरदायी थी।

वर्ष 1920 से 1925 के बीच आर ने विचाराधीन भूमि का अधिग्रहण किया, लेकिन आर के कहने पर वार्ड न्यायालय द्वारा पी, जी और एन के नाम पर उनका बेनामी निपटारा किया गया। 1934 में आर की मृत्यु के बाद भूमि के स्वामित्व को लेकर विवाद उत्पन्न हुए और उनके कानूनी प्रतिनिधियों, अपीलकर्ताओं ने पी और जी और एन के कानूनी प्रतिनिधियों, प्रत्यर्थियों के खिलाफ भूमि पर अपने अधिकार की घोषणा करने और कब्जा करने के लिए एक मुकदमा दायर किया, इस आधार पर कि प्रत्यर्थियों के पास बेनामीदारों के रूप में वाद भूमि का कब्जा था। यह पाया गया कि (आर) इन भूमि के अधिग्रहण के लिए विचार आर से आगे बढ़ा था, जिसने उन्हें अपने रिश्तेदारों के नाम पर बसाया था, लेकिन पट्टा के खंड 4 और 16 के संचालन से बचने के लिए वार्ड के न्यायालय को यह सूचित नहीं किया कि वे उसके रिश्तेदार थे, (2) कि भूमि के निपटान के लिए आवेदन पत्रों पर पी, जी और एन द्वारा हस्ताक्षर नहीं किए गए थे, बल्कि! उत्तराधिकारी के नाम किसी और द्वारा लिखे गए थे, और (3) पट्टा आर की अवधि समाप्त होने से पहले वार्ड के न्यायालय को लेनदेन की बेनामी प्रकृति के बारे में सूचित किया गया था, लेकिन वार्ड के न्यायालय ने खंड 16 को लागू नहीं किया था। प्रत्यर्थियों ने अन्य बातों के साथ-साथ तर्क दिया कि अपीलकर्ताओं द्वारा स्वयं यह दर्शाते हुए कि भूमि का निपटारा वार्ड न्यायालय पर धोखाधड़ी करने के लिए बेनामी किया गया था, अपीलार्थी निर्णय के हकदार नहीं थे, और (2) इन भूमि का अधिग्रहण

पी, जी और एन के जाली हस्ताक्षरों के माध्यम से प्राप्त किया गया था, अपीलार्थी, किसी भी मामले में, इस उक्ति के आवेदन पर, सफल होने के हकदार नहीं थे।

अभिनिर्धारित किया गयाः

(1) कि मामले के तथ्यों पर, धोखाधड़ी, हालांकि इसका इरादा किया गया था, को अंजाम नहीं दिया गया था, क्योंकि यह केवल पट्टे की अवधि के अंत में ही प्रभावी हो सकता था और पट्टेदार के पास जो अधिकार था, उसका पट्टे की समाप्ति से बहुत पहले विधिवत उपयोग किया गया था। इसलिए, अपीलकर्ताओं को उत्तरदाताओं से भूमि की वसूली करने का अधिकार नहीं था, जो केवल बेनामीदार पाए गए थे।

(2) कि कानून में सही स्थिति यह है कि किसी को यह देखना होगा कि क्या अवैधता मामले की जड़ तक जाती है कि वादी उस अवैध लेनदेन पर भरोसा किए बिना अपनी कार्रवाई नहीं कर सकता है जिसमें उसने प्रवेश किया था। यदि अवैधता तुच्छ या तुच्छ है और वादी को उस अवैधता पर अपने मामले को स्थगित करने की आवश्यकता नहीं है, तो सार्वजनिक नीति की मांग है कि प्रतिवादी को स्थिति का लाभ उठाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। बेशक, वादी के आचरण के बारे में एक सख्त दृष्टिकोण रखा जाना चाहिए, और उसे किसी छल का सहारा लेकर या तथ्यों को गलत तरीके से पेश करके अवैधता को दरकिनार करने की

अनुमति नहीं दी जानी चाहिए यदि, हालांकि मामला स्पष्ट है और अवैधता को कार्रवाई के कारण के हिस्से के रूप में अभिवचन या साबित करने की आवश्यकता नहीं है और वादी ने अवैध उद्देश्य को प्राप्त करने से पहले पीछे हट गया है, तो जब तक कि यह अदालत की अंतरात्मा को अपमानित करने के लिए इतनी घोर प्रकृति का न हो, तब तक प्रतिवादी की याचिका प्रबल होनी चाहिए।

वर्तमान मामले में अवैधता एक तुच्छ चरित्र की थी, क्योंकि पी और अन्य लोगों के हस्ताक्षर अपीलार्थियों की घनिष्ठ मित्रता और संबंध के विश्वास पर किए गए थे और इस धारणा के तहत कि उनकी ओर से आवेदन करने और उनके नाम पर प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करने पर कोई आपत्ति नहीं होगी। अपीलार्थियों को अपनी कार्रवाई के कारण के हिस्से के रूप में इस तथ्य को साबित करने कीआवश्यकता नहीं थी और वास्तव में, यदि उत्तरदाताओं पर विश्वास किया जाए, तो उन्होंने जोर देकर कहा कि हस्ताक्षर जाली नहीं थे, बल्कि उनके अपने थे, तदनुसार, अपीलार्थी मुकदमा करने और अपने पक्ष में एक डिक्री प्राप्त करने के हकदार थे।

सिविल अपीलीय अधिकारिता : सिविल अपील सं. 151/1955

अतिरिक्त उप-न्यायाधीश, मोतिहारी, 1944/45 के शीर्षक सूट संख्या 42/12 में 29 मार्च, 1946 के निर्णय और डिक्री से उत्पन्न और पटना

उच्च न्यायालय के 1946 की मूल डिक्री संख्या 273 में 6 मार्च, 1952 के निर्णय और डिक्री से अपील।

अपीलार्थियों की ओर से एन. सी. चटर्जी और आर. सी. प्रसाद।

उत्तरदाताओं के लिए ए. वी. विश्वनाथ शास्त्री और बी. पी. माहेश्वरी।

1959, 25 सितंबर

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला द्वारा दिया गया-

पटना उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए प्रमाण पत्र के साथ यह अपील उसके 6 मार्च, 1952 के फैसले और डिक्री के खिलाफ दायर की गई है। उस फैसले से उच्च न्यायालय ने 29 मार्च, 1946 के मोतिहारी के अधीनस्थ न्यायाधीश के आदेश को उलट दिया।

वर्तमान अपीलकर्ताओं द्वारा रायोती पश्त भूमि के 136 बीघा पर अपने अधिकार की घोषणा करने और प्रतिवादियों के साथ विशेष रूप से या संयुक्त रूप से उस पर कब्जा करने के लिए मुकदमा दायर किया गया था। समान लाभ और ब्याज के लिए भी दावा किया गया था। मुक़दमे का फैसला अधीनस्थ न्यायाधीश, मोतिहारी द्वारा इस आधार पर किया गया था कि प्रतिवादी बेनामीदारों के रूप में मुक़दमे की भूमि के कब्जे में थे। ट्रायल जज ने पाया कि इन भूमि के अधिग्रहण के लिए विचार वादी के पूर्ववर्ती से आगे बढ़ा था, जिन्होंने उन्हें प्रहलाद राय, गुलराज राय और

नवरंग राय के फरज़ी नामों से अधिग्रहित किया था। उन्होंने यह भी माना कि बेनामीदार शादी से राधुमल से संबंधित थे, और राधुमल को उनके नामों का उपयोग करना सुविधाजनक लगा। इन निष्कर्षों को उच्च न्यायालय में वर्तमान उत्तरदाताओं द्वारा स्वीकार किया गया था। हालाँकि, उन्होंने उच्च न्यायालय के समक्ष ट्रायल जज द्वारा उनके खिलाफ पाए गए कुछ तर्कों को उठाया। याचिका में अपीलकर्ताओं ने प्रह्लाद राय, गुलराज राय और नवरंग राय के नाम से संपत्ति बेनामी हासिल करने के अपने कारण बताए थे। उन्होंने कहा था कि पट्टे की शर्तों के अनुसार, पट्टेदार या उसके रिश्तेदारों और नौकरों के नाम पर ली गई रैयती भूमि पट्टे की समाप्ति के बाद बेतिया राज द्वारा फिर से शुरू की जानी चाहिए और इस आकस्मिकता से बचने के लिए बेनामी लेनदेन किया गया था। इसलिए, उत्तरदाता प्रत्यर्थियों ने प्रथम दृष्टांत न्यायालय में तर्क दिया कि अपीलकर्ताओं के पूर्ववर्ती ने बेतिया राज पर धोखाधड़ी करने के लिए बेतिया राज बेनामी द्वारा इन भूमि को उनके नाम पर बसाया था, और धोखाधड़ी सफल होने के बाद, वादी-अपीलकर्ता निर्णय के हकदार नहीं थे। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि बेतिया राज के साथ अपीलकर्ताओं के पट्टे की समाप्ति के बाद इन भूमि को उनके साथ निपटाया गया था या उनके साथ निपटाया गया था। इन दोनों आधारों को उच्च न्यायालय ने स्वीकार कर लिया था।

इस न्यायालय में, प्रत्यर्थियों ने एक ही रुख अपनाया है, और यह भी तर्क दिया है कि इन भूमि का अधिग्रहण प्रहलाद राय, गुलराज राय और नवरंग राय के जाली हस्ताक्षरों के माध्यम से प्राप्त किया गया है, वर्तमान अपीलार्थी उक्ति के आवेदन पर निर्णय के हकदार नहीं हैं। हालाँकि, उनका तर्क है कि यदि न्यायालय का यह विचार है कि दोनों पक्षों ने बेतिया राज को धोखा देने की साजिश रची थी या वे अवैधता के दोषी थे, तो भी प्रतिवादी की स्थिति बेहतर होगी।

नीचे दिए गए दोनों न्यायालयों के निर्णयों और उत्तरदाताओं की रियायत से, तथ्य के सभी प्रश्नों को अंतिम रूप से तय किया जाना चाहिए। यह प्रश्न कि क्या अधिग्रहण बेनामी था या नहीं, अब फिर से नहीं खोला जा सकता है, और इसलिए मामले पर केवल उपरोक्त अनुसिद्धांतों में निहित सिद्धांतों और इस तथ्य के संबंध में विचार किया जाना चाहिए कि क्या बेतिया राज पर कोई धोखाधड़ी का इरादा था और, यदि हां, तो क्या यह प्रभावित हुआ था और इसके लिए कौन जिम्मेदार था।

यद्यपि मामले का निर्णय बहुत ही संकीर्ण दायरे में प्रतीत हो सकता है, लेकिन इन अधिग्रहणों के इतिहास पर असर डालने वाले व्यापक तथ्यों को फिर से गिनाना आवश्यक है। **1** अप्रैल, **1922** को, कोर्ट ऑफ वार्ड्स के प्रबंधक, बेतिया राज ने, रधुमल को, जो अब संयुक्त परिवार के कर्ता थे, **10** वर्षों के लिए बिजबनिया गांव का पट्टा दिया (असिन **1327** से भादो

1336, उदाहरण **7** के अनुसार)। वादी और महादेव**,** प्रतिवादी **6** द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया। **26** जून**, 1931** को**,** पट्टे को **10** साल **(1337** से **1346)** की एक और अवधि के लिए नवीनीकृत किया गया था। इस पट्टे की दो शर्तों को अगली कड़ी में संदर्भित करना होगा**,** और आसानी से संदर्भ के लिए यहां उद्धृत किया जा सकता है।

"4. प्रबंधक की सहमति के बिना किसी रैयत या अन्य किरायेदार के साथ भूमि का कोई समझौता नहीं करना, और अधिकार के अभिलेख में ज़ीरात या बकश्त के रूप में दर्ज भूमि के किसी भी निपटान के लिए ऐसी सहमति के लिए किसी भी आवेदन में पट्टेदार का ऐसा समझौता करने की इच्छा का कारण बताना, और वह क्षेत्र या ज़ीरात या बकश्त भूमि जो ऐसा समझौता किए जाने के बाद नष्ट की गई संपत्ति में रहेगी, और जब पट्टेदार के किसी रिश्तेदार या नौकर के साथ कोई समझौता करने का प्रस्ताव किया जाता है तो उस तथ्य को बताना; और यह घोषित किया जाता है कि प्रबंधक ऐसे किसी भी समझौते के लिए सहमति देने की शर्त के रूप में हकदार होगा ताकि यह आवश्यक हो कि उसके द्वारा निर्धारित की जाने वाली राशि को किसी भी ऐसे समझौते पर सलामी के रूप में लिया जाएगा।

16. पट्टा अवधि के दौरान निजी खरीद, नीलामी में खरीद, बंधक, उप-पट्टा, समर्पण या अन्यथा द्वारा अर्जित किसी भी रैयती जोत या पट्टे पर

दी गई संपत्ति में अन्य ब्याज के पट्टा की समाप्ति के बाद कब्जा न रखने के लिए, और इस प्रकार अर्जित कोई भी हिस्सेदारी या ब्याज पट्टेदार के पास चला जाएगा, बशर्ते कि पट्टेदार पट्टेदार से किसी भी नुकसान के बराबर राशि प्राप्त करने का हकदार होगा, जो उसे किराया बकाया के लिए नीलामी बिक्री में हिस्सेदारी खरीदने से हो सकता है, खरीद मूल्य के खिलाफ खरीद की तारीख से भूमि से पट्टेदार द्वारा किए गए लाभ की गणना करके गणना की जानी चाहिए, जो राजस्व बोर्ड द्वारा जारी किए जाने वाले किसी भी सामान्य निर्देशों के अधीन है, प्रबंधक कम राशि से प्राप्त होने वाली राशि का निर्धारण करेगा।"

1920 से 1925 के बीच राधुमल ने विभिन्न तरीकों से 136 बीघा भूमि का अधिग्रहण किया, जो अब विवाद का विषय है। कोर्ट सेल में 94 बीघा, निजी बिक्री में 7 बीघा और पिछले किरायेदारों द्वारा किरायेदारी को छोड़कर 6 बीघा खरीदी गई थी। इन 136 बीघा में 27 बीघा भूमि भी शामिल थी, जिन्हें घैर मजरूआ, पट्टी कदीम और काबिल लैगन के रूप में वर्णित किया गया है। इन भूमि को प्रहलाद राय, गुलराज राय और नवरंग राय के साथ बेतिया राज द्वारा बसाया गया था। जवाब देने वाले प्रतिवादी प्रहलाद राय और अन्य दो के कानूनी प्रतिनिधि हैं। इन व्यक्तियों के साथ इन भूमि को निपटाने में, राधुमल ने स्वयं पट्टेदार के रूप में बेतिया राज को उनकी सिफारिश की, और अब यह साबित हो गया है और मामले में स्वीकार किया गया है कि उन्होंने बेतिया राज में दायर दस्तावेजों पर इन

व्यक्तियों के हस्ताक्षर भी किए थे। जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है, इस उपकरण का सहारा लिया गया था, ताकि ऊपर उद्धृत पट्टे के खंड 16 के संचालन से बचा जा सके। इसका उपयोग खंड 4 के तहत बेतिया राज को देय सलामी को कम करने के लिए भी किया जाता था जो एक अजनबी के मामले में पट्टेदार, उसके रिश्तेदारों और नौकरों के मामले में कम था। प्रत्यर्थियों ने इन सभी दलीलों को अस्वीकार कर दिया था, और कहा था कि बेतिया राज द्वारा उनके साथ भूमि का निपटान किया गया था, और वे राधुमल के बेनामीदार नहीं थे। अब वे खंड 16 और 4 के संचालन से भूमि को बचाने के लिए, उपकरण के संबंध में अपीलकर्ताओं द्वारा अनुरोध किए गए तथ्यों पर भरोसा करते हैं और आगे प्रहलाद राय, गुलराज राय और नवरंग राय के हस्ताक्षर करने के लिए राधुमल के अवैध आचरण का अनुरोध करते हैं।

28 फरवरी**, 1934** को रधुमल की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद**,** बाला प्रसाद**,** अपीलकर्ता नंबर **3** को गोद लिया गया**,** और गोद लेने को बेतिया राज द्वारा भी मान्यता दी गई। पट्टा भी बाला के नाम कर दिया गया। ऐसा आरोप है कि **1935** में प्रतिवादी **6** महादेव के कहने पर विधवा ने इस गोद लेने से इनकार कर दिया और बदले में महादेव ने संपत्ति में सभी हितों से इनकार करना शुरू कर दिया। अन्य उत्तरदाताओं ने भी रधुमल के उत्तराधिकारियों और प्रतिनिधियों के विरुद्ध अपना स्वामित्व जताना शुरू कर दिया। यह भी आरोप लगाया गया था कि महादेव ने सभी

कैबला और कुछ रसीदें हटा दी थीं और उन्हें प्रह्लाद राय को दे दी थीं, जिनका उपयोग उत्तर देने वाले उत्तरदाताओं ने बाद की सभी कार्यवाही में किया था। **1936** में, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा **144** के तहत कार्यवाही शुरू की गई, जो **4** जून, **1936** को उपमंडल अधिकारी के एक आदेश द्वारा प्रह्लाद राय की पार्टी के पक्ष में समाप्त हो गई। जिला मजिस्ट्रेट, चंपारण द्वारा उलट दिया गया, और उच्च न्यायालय में पुनरीक्षण पर, जिला मजिस्ट्रेट के निष्कर्ष को उलट दिया गया, हालांकि नियम को ही खारिज कर दिया गया था। उच्च न्यायालय ने शांति भंग होने की आशंका होने पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा **145** के तहत कार्यवाही शुरू करने की सिफारिश की। ये कार्यवाही अपीलकर्ताओं के खिलाफ एक आदेश द्वारा शुरू की गई और अंततः मई, **1842** को समाप्त कर दी गई, जो इसलिए इस मुकदमे को लाने के लिए मजबूर थे क्योंकि उनके अनुसार, आपराधिक अदालतों में फैसले ने उनके शीर्षक पर एक बादल डाल दिया था।

वर्तमान मामले में विवाद जिस मुख्य मुद्दे के इर्द-गिर्द घूमता है, वह पाँचवाँ है, जिसे अधीनस्थ न्यायाधीश द्वारा तैयार किया गया है। वह इस प्रकार हैः

"क्या प्रतिवादी वाद की भूमि के संबंध में वादी के फ़र्ज़ीदार हैं**?"**

जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, इस मुद्दे पर अब अंततः अपीलार्थियों के पक्ष में निर्णय लिया गया है। उच्च न्यायालय ने

अभिनिर्धारित किया है कि इस निष्कर्ष के बावजूद वे इस आधार पर निर्णय के हकदार नहीं हैं कि उन्होंने बेतिया राज के साथ धोखाधड़ी की थी और यह धोखाधड़ी उन्हें निर्णय के लिए अयोग्य बनाती है। उच्च न्यायालय ने यह भी कहा है कि पट्टा समाप्त होने के बाद, उत्तरदाताओं को बेतिया राज के रैयती किरायेदार माना जाना चाहिए, क्योंकि उनसे किराया स्वीकार किया गया था न कि पट्टेदार से। उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीशों में से एक ने मुख्य रूप से इस आधार पर मामले का फैसला किया, लेकिन विद्वान मुख्य न्यायाधीश ने दोनों बिंदुओं पर कारण बताए। विद्वान मुख्य न्यायाधीश ने इस तथ्य पर भी जोर दिया कि राधुमल द्वारा की गई कुछ अवैधताएँ थीं, जिसने उत्तरदाताओं की स्थिति को मजबूत बना दिया।

हम राधुमल को दिए गए पट्टे की समाप्ति के बाद बेतिया राज द्वारा एक नई किरायेदारी के निर्माण के मुद्दे से शुरू करते हैं। हम यह इंगित कर सकते हैं कि मामले के इस पहलू का जवाब देने वाले उत्तरदाताओं द्वारा अनुरोध नहीं किया गया था, और इस मामले को स्वीकार करना मुश्किल है, जिसके लिए एक निष्कर्ष के लिए नए सबूत और सामग्री की आवश्यकता होती है। उत्तरदाताओं का मामला यह था कि उन्होंने शुरुआत में ही बेतिया राज से इन भूमि का निपटान ले लिया था। इसलिए, उनके साथ एक नए समझौते के लिए कोई अवसर नहीं था, और यह दलील कि पट्टे की समाप्ति के बाद, वास्तव में, या कानून में माना जाना चाहिए, उनके साथ एक नया समझौता, उनके लिए खुला नहीं है। इस मामले में

यह दिखाने के लिए सबूत हैं कि राधुमल को दिए गए पट्टे की समाप्ति के बाद एक बार फिर बी. एच. फॉर्म जारी नहीं किए गए थे। आर. एन. प्रसाद (पीडब्लू. 3) ने कहा कि बी. एच. प्रपत्र की एक प्रमाणित प्रति जिसके तहत भूमि का निपटान एक रैयती किरायेदार के साथ किया गया था, उसकी जानकारी के लिए निपटान को जारी किया गया था, और उत्तरदाताओं द्वारा ऐसा कोई नया बी. एच. प्रपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इन दो तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, हमें यह कहना चाहिए कि उच्च न्यायालय ने उत्तरदाताओं के लिए एक नया मामला बनाने में गलती की थी। अपील में किसी अदालत के लिए यह खुला नहीं है कि वह किसी पक्ष द्वारा नहीं की गई मीडिया की दलीलों पर विचार करे और उनके आधार पर निर्णय दे।

यह दो कहावतों और बेतिया राज में की गई धोखाधड़ी के प्रश्न पर विचार करने के लिए छोड़ दिया गया है। पारि डिलिक्टो आदि में उक्ति को इस संदर्भ में शायद ही लागू किया जा सकता है। न तो अपीलकर्ताओं और न ही प्रत्यर्थियों ने किसी भी समय यह दलील दी कि प्रहलाद राय, गुलराज राय और नवरंग राय ने बेतिया राज पर धोखाधड़ी करने की साजिश रची। इस संबंध में, अपीलार्थियों और प्रत्यर्थियों के मामले अलग-अलग हैं। जबकि अपीलकर्ताओं का दावा है कि राधुमल ने इन तीन व्यक्तियों की सहमति प्राप्त करना भी आवश्यक नहीं समझा और यहां तक कि उनके हस्ताक्षर भी प्राप्त नहीं किए, उत्तरदाताओं का दावा है कि राधुमल का इन

भूमि के अधिग्रहण से कोई लेना-देना नहीं था और उन्होंने पट्टेदार के रूप में केवल बेतिया राज को उनकी सिफारिश की थी। जहां दोनों पक्ष यह नहीं दिखाते हैं कि किसी तीसरे व्यक्ति को धोखा देने या कोई अन्य अवैध कार्य करने की कोई साजिश थी, तो पारि डिलिक्टो आदि में उक्ति को शायद ही लागू किया जा सकता है। अपीलार्थी और उत्तरदाता समान अधिकार में नहीं थे। उत्तरदाताओं ने निर्दोष पक्ष होने का दावा किया, जिन्होंने स्वयं भूमि का अधिग्रहण किया था, और दूसरी ओर, अपीलकर्ताओं ने कहा कि उत्तरदाताओं को इस मामले के बारे में कुछ भी पता नहीं था और उनसे परामर्श भी नहीं किया गया था। हमारी राय में, उक्ति का प्रयोग गलत था।

यह सबसे पहले विचार करने के लिए छोड़ देता है कि क्या बेतिया राज पर धोखाधड़ी की गई थी, और क्या यह सफल रहा था। अपीलकर्ताओं का तर्क है कि बेतिया राज के पास यह जानकारी पूरी तरह से थी कि यह एक बेनामी लेनदेन था और सलामी 1, 680 रुपये के हिसाब से प्राप्त की गई थी। और केवल उन भूमि के संबंध में माफ किया गया था जो सलामी की मांग के योग्य नहीं मानी जाती थी। अपीलार्थियों द्वारा साक्ष्य में कहा गया है कि बेतिया राज को लेन-देन की बेनामी प्रकृति के बारे में सूचित किया गया था और बेतिया राज के सहायक प्रबंधक राय बहादुर मोतीलाल बसु, जो कोर्ट ऑफ वार्ड के तहत थे, को इसके बारे में सूचित किया गया था। आर. एच. प्रसाद (पीडब्लू. 3) ने कहा कि राय बहादुर मोती लाल बसु

एस्टेट के सहायक प्रबंधक थे और वे एक अनुभवी अधिकारी थे। नारायण लाल, (P.W.17) ने अपदस्थ कर दिया कि उनकी उपस्थिति में राधुमल ने मोती लाल बसु से कहा था कि वह अपने संबंधों के फरज़ी नामों पर समझौते कर रहे हैं। यह भी स्पष्ट है कि 1936 में जब विवाद जिला मजिस्ट्रेट, चंपारण के पास गया, तो इन सभी तथ्यों को दोनों पक्षों के प्रतिद्वंद्वी मामलों में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 और 145 के तहत निर्धारित किया गया था। जिला मजिस्ट्रेट कोर्ट ऑफ वार्ड्स के एक अधिकारी थे, और उन्हें 1936 तक पता था कि किरायेदारों को राधुमल द्वारा बेनामी लिया गया था। पट्टा की समाप्ति के बाद, वार्ड न्यायालय ने इस जानकारी के बावजूद खंड 16 को लागू नहीं किया, और इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि धोखाधड़ी प्रभावित नहीं हुई थी, क्योंकि धोखाधड़ी करने वाला व्यक्ति या प्राधिकरण सभी तथ्यों को जानता था, और उसने कोई कार्रवाई नहीं करने का फैसला किया। शिकायत में अपीलार्थियों के बयान के अलावा अभिलेख में ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह दर्शाता हो कि सलामी अनुचित रूप से कम थी। दूसरी ओर, उत्तरदाताओं ने दावा किया कि उन्होंने अपने स्वयं के धन से उचित सलामी का भुगतान किया है। हालाँकि, यह माना गया है कि राधुमल ने सलामी का भुगतान किया था, एक तथ्य जिस पर अब सवाल नहीं उठाया गया है। प्रतिद्वंद्वी प्रवेश एक-दूसरे को रद्द कर देते हैं और मामले को बड़े पैमाने पर छोड़ देते हैं। इस मामले को कभी भी मुद्दे में नहीं रखा गया, सिवाय इसके कि किसने

सलामी का भुगतान किया और सलामी की पर्याप्तता या अन्यथा कभी भी कोशिश नहीं की गई। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि धोखाधड़ी को प्रभावित नहीं कहा जा सकता है, हमें नहीं लगता कि जिन अपीलार्थियों ने लेनदेन की बेनामी प्रकृति को स्पष्ट रूप से स्थापित किया है, उन्हें उनके निर्णय से वंचित किया जा सकता है। अधिकारी उस हद तक नहीं जाते हैं, क्योंकि सार्वजनिक नीति की मांग है कि जहां धोखाधड़ी पर विचार किया गया हो, लेकिन उसे अंजाम नहीं दिया गया हो, तो प्रतिवादियों को एक नई धोखाधड़ी करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

अब इस प्रश्न पर आते हुए कि क्या उच्च न्यायालय द्वारा उक्ति, पूर्व कारण आदि के आवेदन पर अपीलार्थियों के मुकदमे को सही ढंग से खारिज कर दिया गया था, हमें पहले यह देखना होगा कि कौन से विशिष्ट तथ्य हैं जिन पर यह विवाद आधारित है। अपीलार्थियों का मामला यह था कि खंड 16 के निहितार्थ से बचने के लिए संपत्ति को प्रह्लाद राय और अन्य लोगों के नाम पर बेनामी लिया गया था। बेतिया राज को आवेदन देने में प्रह्लाद राय और अन्य लोगों के हस्ताक्षर राधुमल या उनके निर्देश पर किसी ने किए थे, क्योंकि राधुमल, प्रह्लाद राय और अन्य लोगों के बीच संबंध इतने अंतरंग थे कि उन्हें परेशान करना अनावश्यक माना जाता था। चूंकि मामला वार्ड न्यायालय के सहायक प्रबंधक के संज्ञान में लाया गया था, इसलिए इन सभी तथ्यों की जांच की जा सकती थी, जिसमें राधुमल द्वारा हस्ताक्षर करना भी शामिल था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि

किसी अन्य व्यक्ति की सहमति, व्यक्त या निहित के बिना हस्ताक्षर करना सामान्य कानून के तहत एक अपराध है, लेकिन इरादा जाली हस्ताक्षर करने का नहीं था, बल्कि उन व्यक्तियों के नाम पर आवेदन प्रस्तुत करने का था। हालाँकि, हम इस धारणा पर आगे बढ़ते हैं कि बेतिया राज से संपर्क करने और बी. एच. प्रपत्रों के निष्पादन में भी राधुमल द्वारा कुछ अवैधता की गई थी, जिन पर इन व्यक्तियों के नामों के साथ हस्ताक्षर भी किए गए थे। सवाल यह है कि क्या यह अवैधता उक्ति के आवेदन पर वादी पर गैर-मुकदमा करने के लिए पर्याप्त है।

लॉर्ड मैन्सफील्ड ने 1775 में होल्मन बनाम जॉनसन (1) में निम्नलिखित शब्दों में कहा थाः

"सार्वजनिक नीति का सिद्धांत यह है; ("धोखाधड़ी से कोई कार्रवाई उत्पन्न नहीं होती") कोई भी न्यायालय उस व्यक्ति को अपनी सहायता नहीं देगा जो किसी अनैतिक या अवैध कार्य पर अपनी कार्रवाई का कारण पाता है। यदि, वादी के अपने कथन या अन्यथा से, कार्रवाई का कारण पूर्व कारण या इस देश के सकारात्मक कानून का उल्लंघन प्रतीत होता है, तो न्यायालय कहता है कि उसे सहायता प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं है। यह उस आधार पर है जिस पर न्यायालय जाता है; प्रतिवादी के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि वे ऐसे वादी को अपनी सहायता नहीं देंगे। इसलिए यदि वादी और प्रतिवादी पक्ष बदलते हैं, और प्रतिवादी को वादी के खिलाफ

अपनी कार्रवाई करनी है, तो बाद वाले को इसका लाभ होगा; क्योंकि जहां दोनों समान रूप से दोषी हैं, तो बचाव पक्ष की स्थिति बेहतर होगी।"

हालाँकि, तुर्पी कौसा के नियम के कुछ अपवाद या "कथित अपवाद" हैं। अनुबंधों पर सैल्मंड और विलियम में, ऐसे चार अपवादों का उल्लेख किया गया है, और इनमें से चौथा अपवाद एकीकरण में पुनर्स्थापन के अधिकार पर आधारित है, जहां न्यासी और लाभार्थी का संबंध शामिल है। सैल्मंड ने अपनी पुस्तक (दूसरा संस्करण) के पृष्ठ 352 पर इन शब्दों में कानून का उल्लेख किया हैः

"इसलिए यदि ए डकैती करने के लिए बी को नियुक्त करता है, तो ए आय के लिए बी पर मुकदमा नहीं कर सकता है। और स्थिति वही होगी यदि ए किसी धोखाधड़ी की योजना को पूरा करने के लिए ट्रस्ट पर बी में संपत्ति निहित करता हैः ए लाभ के खाते के लिए बी पर मुकदमा नहीं कर सकता था। लेकिन यदि बी, जो ए का अभिकर्ता या न्यासी है, ए के खाते में ए और सी के बीच एक अवैध अनुबंध के अनुसार सी द्वारा भुगतान किया गया धन प्राप्त करता है, तो स्थिति अन्यथा है और ए बी से संपत्ति की वसूली कर सकता है, हालांकि वह सी से इसका दावा नहीं कर सकता था। ऐसे मामलों में सार्वजनिक नीति के लिए आवश्यक है कि टर्पिस कौसा के नियम को अधिक महत्वपूर्ण और अनिवार्य नियम द्वारा बाहर रखा

जाएगा कि एजेंटों और न्यासियों को ईमानदारी से अपने कार्यालय के कर्तव्यों का पालन करना चाहिए।"

विलिस्टन ने अपनी पुस्तक ऑन कॉन्ट्रैक्ट्स (संशोधित संस्करण), खंड VI में, पृष्ठ 5069, पैरा 1785 और पैरा 1771 से 177 4 में इस मामले पर चर्चा की है, उन्होंने कुछ असाधारण मामलों का उल्लेख किया है, और निम्नानुसार देखा है:

"यदि किसी भी मामले में किसी भी भागीदार या मूलधन द्वारा वसूली की अनुमति दी जानी है, तो यह होना चाहिए जहां अवैधता इतनी हल्की या अश्लील प्रकृति की हो कि प्रतिवादी को वादी के साथ अपने प्रत्ययी संबंध का उल्लंघन करने की अनुमति देना सार्वजनिक नीति का अधिक विरोध माना जाए, बजाय इसके कि वादी को अवैध लेनदेन का लाभ प्राप्त करने की अनुमति दी जाए।"

भारत में भी तुर्पी कौसा के नियम के कुछ अपवादों को स्वीकार किया गया है। उन मामलों के उदाहरण पलनियप्पा चेट्टियार बनाम चोकलिंगम चेट्टियार (1) और भोला नाथ बनाम मुल चंद (2) में पाए जाते हैं।

उत्तरदाता यह दिखाने के लिए फार्मर्स मार्ट लिमिटेड बनाम मिल्ने (1), अलेक्जेंडर बनाम रेसन (2) और बर्ग बनाम सैडलर और मूर (3) पर भरोसा करते हैं कि यह मामला उन मामलों में स्वीकार किए गए और लागू

किए गए नियम के भीतर आता है। हालाँकि, नियम का अनुप्रयोग एक बात से सशर्त है, अर्थात्, एक वादी जिसे सफल होने की अनुमति नहीं है, वह उसके द्वारा की गई अवैधता के अनुरोध के अलावा किसी कार्रवाई को बनाए रखने में असमर्थ होना चाहिए। फार्मर्स मार्ट लिमिटेड बनाम मिल्ने (1) में लॉर्ड डुनेडिन के भाषण में, तीन मामलों का संदर्भ दिया गया है, सिम्पसन बनाम ब्लॉस (4), फिवाज़ बनाम निकोल्स (5) और टेलर बनाम चेस्टर (6)। पहले मामले में, यह निर्धारित किया गया था कि परीक्षण यह था कि क्या एक अवैध लेनदेन से जुड़ी मांग कानून में लागू होने में सक्षम थी, और क्या वादी को अपने मामले को स्थापित करने के लिए अवैध लेनदेन से किसी सहायता की आवश्यकता थी। टिंडल, सी. जे., ने दूसरे मामले में निम्नलिखित टिप्पणी कीः

"मेरा मानना है कि इस मामले का निर्धारण इस संक्षिप्त आधार पर किया जा सकता है कि वादी अपने और प्रतिवादी के बीच मूल रूप से किए गए अवैध समझौते पर भरोसा किए बिना, रिकॉर्ड पर बताए गए अपने दावे को स्थापित करने में असमर्थ है।"

अंतिम मामले में, जे. मेलर ने कहा कि सही परीक्षा इस बात पर विचार करके थी कि "क्या वादी अपने मामले को माध्यम के अलावा और उस अवैध लेनदेन की सहायता से बना सकता है जिसमें वह स्वयं एक पक्ष था।" अलेक्जेंडर बनाम रेसन (2) में, अपील न्यायालय द्वारा यह

अभिनिर्धारित किया गया था कि धोखाधड़ी या अवैधता को अंजाम देने से पहले पश्चाताप का अधिकार होना चाहिए।

हाल ही में, बोमेकर्स लिमिटेड बनाम बार्नेट इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड **(1)** में अपील की अदालत ने इस विषय पर कानून की समीक्षा की, और निर्धारित किया कि प्रत्येक अवैधता अदालत को वादी को निर्णय देने से इनकार करने का अधिकार नहीं देती है। डू पारक, एल.जे., ने इस रूप में देखाः

"हमारी राय में, एक व्यक्ति का अपनी संपत्तियों को रखने का अधिकार एक सामान्य नियम के रूप में उस व्यक्ति के खिलाफ लागू किया जाएगा, जो बिना किसी अधिकार के, उन्हें हिरासत में ले रहा है, या उन्हें अपने उपयोग में बदल दिया है, भले ही यह या तो अभिवचनों से या मुकदमे के दौरान प्रतीत हो सकता है कि विचाराधीन संपत्तियां प्रतिवादी के कब्जे में उसके और वादी के बीच एक अवैध अनुबंध के कारण आई हैं, बशर्ते कि वादी अवैध अनुबंध पर अपना दावा करने या अपने दावे का समर्थन करने के लिए इसकी अवैधता का अनुरोध करने के लिए मजबूर न हो।"

हम जानते हैं कि प्रोफ़ेसर हैम्सन ने (1949) 10 कैम्ब्रिज लॉ जर्नल, 249 में इस मामले की आलोचना की है और स्पष्टतम संभावित परिस्थितियों को छोड़कर, इसके आवेदन को खारिज कर दिया है। प्रिटचार्ड,

जे. द्वारा बिगॉस बनाम बौस्टेड (1) में भी कानून पर विचार किया गया है, जिसमें सभी अधिकारियों का उल्लेख किया गया है।

हमारी राय में, कानून में सही स्थिति यह है कि किसी को यह देखना होगा कि क्या अवैधता मामले की जड़ तक जाती है कि वादी उस अवैध लेनदेन पर भरोसा किए बिना अपनी कार्रवाई नहीं कर सकता है जिसमें उसने प्रवेश किया था। यदि अवैधता तुच्छ या तुच्छ है, जैसा कि विलिस्टन ने कहा है और वादी को उस अवैधता पर अपना मामला समाप्त करने की आवश्यकता नहीं है, तो सार्वजनिक नीति की मांग है कि प्रतिवादी को स्थिति का लाभ उठाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। बेशक, वादी के आचरण के बारे में एक सख्त दृष्टिकोण रखा जाना चाहिए, और उसे किसी छल का सहारा लेकर या तथ्यों को गलत तरीके से बताकर अवैधता को दरकिनार करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। हालाँकि, यदि मामला स्पष्ट है और अवैधता को कार्रवाई के कारण के हिस्से के रूप में अभिवचन या साबित करने की आवश्यकता नहीं है और वादी को अवैध उद्देश्य प्राप्त करने से पहले वापस ले लिया गया है, तो, जब तक कि यह इस तरह की स्थूल प्रकृति का न हो कि अदालत की अंतरात्मा को आहत करने के लिए, प्रतिवादी की याचिका प्रबल नहीं होनी चाहिए।

हमें याद रखना चाहिए कि भारत में बेनामी लेन-देन आम बात है और इसे हमेशा मान्यता दी गई है। वे विभिन्न कारणों से दर्ज किए जाते

हैं, और बेनामीदार अपने प्रधान के लिए संपत्ति को ट्रस्ट में रखता है। वर्तमान मामले में, बेनामी लेन-देन का उद्देश्य केवल राधुमल के पक्ष में पट्टे की समाप्ति पर बेतिया राज द्वारा संपत्ति को फिर से शुरू करने से रोकना था, जो निस्संदेह बेताह राज कर सकता था, अगर वह प्रह्लाद राय की तरह था। बेनामी लेन-देन के बारे में जानकारी, हालांकि, फ़िलदायतुल्ला जे. बेतिया राज से नहीं ली गई थी, और उस जानकारी के साथ भी, बेतिया राज ने राधुमल या बेनामीदारों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। राज के कार्रवाई करने के अवसर से पहले वादी ने अपने सही नाम और सही तथ्यों पर जोर दिया। इस प्रकार, धोखाधड़ी, हालांकि इरादा था, को अंजाम नहीं दिया गया था, क्योंकि धोखाधड़ी केवल पट्टे की अवधि के अंत में ही की जा सकती थी, और पट्टेदार के पास जो अधिकार था, उसका उपयोग पट्टे की समाप्ति से बहुत पहले विधिवत किया गया था। अवैधता भी एक तुच्छ चरित्र की थी, क्योंकि प्रह्लाद राय और अन्य लोगों के हस्ताक्षर उनकी घनिष्ठ मित्रता और संबंधों के विश्वास पर संबंधित दस्तावेजों पर किए गए थे और इस धारणा के तहत कि उनकी ओर से आवेदन करने और उनके नाम पर बी. एच. प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करने पर कोई आपत्ति नहीं होगी। अपीलार्थियों को इस तथ्य को अपनी कार्रवाई के हिस्से के रूप में साबित करने की आवश्यकता नहीं थी, और वास्तव में, यदि उत्तर देने वाले उत्तरदाताओं पर विश्वास किया जाए, तो उन्होंने जोर देकर कहा कि हस्ताक्षर जाली नहीं थे, बल्कि वे उनके अपने थे।

लेन-देन की बेनामी प्रकृति को स्थापित करने में, साबित करने के लिए मुख्य बिंदु धन का स्रोत है और यह किया गया था, और यह भी स्थापित किया गया था कि प्रह्लाद राय और अन्य केवल फरज़ीदार थे। इन बातों को साबित करने के लिए, हस्ताक्षर के प्रमाण की आवश्यकता नहीं थी, और हमें नहीं लगता कि वादी लेनदेन की बेनामी प्रकृति का मामला नहीं बना सके, इस अतिरिक्त तथ्य पर भरोसा किए बिना कि प्रह्लाद राय और अन्य लोगों के हस्ताक्षर आवेदन और प्रपत्रों पर उनकी जानकारी के बिना किए गए थे।

हम सोचते हैं कि वर्तमान मामले में उक्ति के अनुप्रयोग के लिए कोई जगह नहीं है, इसकी सभी कठोरता में, और असाधारण मामले, जिसे हमने संदर्भित किया है, लागू किया गया है। तदनुसार हमारा विचार है कि अपीलकर्ताओं ने इन संपत्तियों के बेनामी अधिग्रहण के अपने मामले को साबित कर दिया है-एक ऐसा मामला जिस पर अब सवाल नहीं उठाया गया है-यह तथ्य कि कुछ सापेक्ष दस्तावेजों पर प्रहलाद राय और अन्य लोगों के हस्ताक्षर उनके अपने नहीं थे, दस्तावेज़ों को उनके अपने नहीं होने से वंचित नहीं कर सकते हैं, वादी-अपीलकर्ताओं को डिक्री के लिए अयोग्य नहीं ठहरा सकते हैं। उक्ति में निहित नियम के अपवादों पर उच्च न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया गया था, जो पूरी तरह से इस धारणा पर आगे बढ़ा कि प्रत्येक अवैधता या धोखाधड़ी ने वादी को निर्णय के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है। हालाँकि, यह कानून नहीं है। हम तदनुसार

मानते हैं कि अपीलार्थी अपने पक्ष में एक डिक्री के हकदार थे, और इस संबंध में, उच्च न्यायालय द्वारा इसे गलत तरीके से अस्वीकार कर दिया गया था।

हम पटना उच्च न्यायालय के निर्णय और डिक्री को दरकिनार करते हैं, और अधीनस्थ न्यायाधीश, मोतिहारी के निर्णय को बहाल करते हैं। इस मामले की परिस्थितियों में, हम सोचते हैं कि हमें इस अपील की लागत के बारे में कोई आदेश नहीं देना चाहिए।

अपील की अनुमति दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।

अस्वीकरण - इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।